

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2355
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

केंद्रीय विद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत और रिक्त शिक्षण पद

†2355. श्री नवीन जिंदल:

श्री अजय भट्ट:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्तराखंड सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान-वार विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में रिक्त पड़े स्वीकृत शिक्षण पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से आकांक्षी जिलों, जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में इन रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर या समयबद्ध तरीके से भरने का है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'निपुण' भारत और अन्य बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान कार्यक्रमों के तहत शिक्षण परिणामों की गुणवत्ता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो मुख्य निष्कर्षों तथा किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान-उन्मुख शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविस) और नवोदय विद्यालय समिति (नविस) जो क्रमशः केंद्रीय विद्यालयों (केवि) तथा नवोदय विद्यालयों (नवि) का प्रबंधन करते हैं एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) तथा केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थान (सीएफटीआई) सहित केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थान (सीएचईआई) शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन हैं। स्वायत्त संस्थानों के रूप में, संकाय सदस्यों

की भर्ती संस्थान के भर्ती नियमों और विनियमों के अनुसार संस्थान के अंदर की जाती है। भर्ती करने का प्राधिकार संबंधित शासी बोर्ड/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास होता है।

रिक्तियां, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थानों, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने और मौजूदा संस्थानों में छात्रों की बढ़ी हुई संख्या तथा क्षमता विस्तार से जनित अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती रहती हैं। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमावली के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते हैं।

केविसं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सितंबर 2022 से जुलाई 2025 तक मिशन भर्ती के दौरान शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से 12,867 नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, नविस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022-23 से दिसंबर 2025 तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 2341 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आकांक्षी जिलों, जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में केवि और नवि में सीधी भर्ती हेतु नवंबर 2025 में केविसं में 8714 और नविस में 5045 शिक्षण पदों की रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। चरण-I और चरण-II परीक्षाएं क्रमशः जनवरी 2026 और मार्च 2026 में आयोजित की गई हैं।

अगस्त 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी सीएचईआई से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए विशेष अभियान चलाएं। सीएचईआई ने रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने भी सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित किया था। अक्टूबर 2025 में सभी सीएचईआई से पुनः मिशन मोड में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया गया है। सितंबर 2022 से, सभी सीएचईआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान चलाया है। दिनांक 23.05.2026 तक (अर्थात् पिछले रोजगार मेले की तारीख), मिशन मोड में 18757 संकाय पदों सहित सभी सीएचईआई द्वारा कुल 32114 पद भरे गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में दूसरी कक्षा तक सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) अर्जित करने को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई

है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 5 जुलाई 2021 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शुरुआती अध्ययन के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाने हेतु राष्ट्रीय बोधपठन एवं संख्याज्ञान (निपुण भारत मिशन) शुरू किया।

इस मिशन के तहत, कई तरह की सुव्यवस्थित पहल की गई हैं। इसमें कक्षा 1 के सभी विद्यार्थियों के लिए तीन माह का स्कूल-रेडीनेस मॉड्यूल विद्या प्रवेश का पूरे देश में कार्यान्वयन करना; निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय पहल)-एफएलएन के माध्यम से बड़े पैमाने पर शिक्षक और स्कूल प्रमुख का प्रशिक्षण, जिसमें गतिविधि-आधारित और बाल-केंद्रित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है; 3-8 वर्ष के बच्चों के लिए दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग)- एफएलएन सामग्री, जादुई पिटारा और ई-जादुई पिटारा जैसे खेल-आधारित और डिजिटल अधिगम संसाधन का प्रावधान; और मातृभाषा में एफएलएन के लिए 121 स्थानीय भाषाओं में तैयार किए गए प्राइमर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को एक ही जगह पर रखने संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 5 सितंबर, 2025 को जारी किए गए हैं, जो स्कूल शिक्षा और आंगनवाड़ियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करते हैं, जिससे प्री-स्कूल से कक्षा 1 में क्रमोन्नयन सरल हो जाता है।

परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) प्रत्येक शैक्षणिक चरण अर्थात् बुनियादी, प्रारंभिक और मिडिल कक्षा 3, 6 और 9 के अंत में विद्यार्थियों की एफएलएन, भाषा और गणित में अधिगम की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। परख का आयोजन प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किया जाता है।

नवीनतम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को आयोजित किया गया था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार परख 2024 रिपोर्ट दिनांक 2 जुलाई, 2025 को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक डोमेन में जारी कर दी गई है। राज्य-वार और जिला-वार प्रदर्शन परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण डैशबोर्ड: <http://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en> पर उपलब्ध है।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के परिणामों से बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान कौशल के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है, जो एनईपी 2020 में परिकल्पित निपुण भारत मिशन के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि ग्रामीण स्कूलों में तीसरी कक्षा के बच्चों का प्रदर्शन शहरी स्कूलों से बेहतर है और बुनियादी चरण पर सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

इसके अतिरिक्त, केविसं अपने संबंधित स्कूलों में विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम के विश्लेषण और शैक्षिक निगरानी के माध्यम से निपुण भारत सहित एफएलएन पहलों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करता है। इस आकलन से क्षमता आधारित शिक्षण द्वारा सहयोग प्रदत्त एफएलएन क्षमताओं, शिक्षक क्षमता निर्माण और सुधारात्मक पहलों में सुधार का पता चलता है। इस आकलन के परिणामों के आधार पर, केविसं ने अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक निगरानी, परामर्श और सुधारात्मक सहायता को और अधिक सुदृढ़ किया है।

(घ) और (ड) केविसं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केविसं कई प्रकार की शिक्षण पद्धतियों जैसे अनुभव-आधारित अधिगम, परियोजना-आधारित अधिगम, कक्षा 6 से 8 के लिए बहु-विषयक परियोजना, विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य के पाठ्यक्रम में व्यावहारिक घटक, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉंग्रेस (एनसीएससी) और मानक इंस्पायर पुरस्कार योजना के तहत परियोजना, विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभागिता, विज्ञान और गणित ओलंपियाड, सीबीएसई चुनौतियां, अटल टिकरिंग प्रयोगशाला, इको क्लब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पहल, फील्ड विज़िट और मिडिल स्टेज के लिए '10 बैगलेस डेज़' पहल और एजुकेशनल टूर के माध्यम से अनुसंधान-उन्मुख शिक्षण और जिज्ञासा एवं समाधान-आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है। ये पहल विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, समालोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, नवाचार, समस्या-समाधान कौशल और अनुसंधान अभिरुचि को बढ़ावा देती हैं।
